स्टार्टअप इकोसिस्टम से करीब 18 लाख लोगों को मिला रोजगार

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 - अंक : 07 - अक्टूबर 2025

सहकारी साखर कारखाना से हो रही कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट व पोटाश ग्रैन्यूल निर्माण इकाई की शुरुआत

सहकारी चीनी मिलों में अब बनेगा

बायोगैस और पोटाश

अहिल्यानगर में शुरू हुआ पहला कारखाना

एनसीईएल के माध्यम से ही निर्यात करें सभी सहकारी संस्थानः श्री शाह आवरण कथा 08

'सहकार से समृद्धि' के विजन को आगे बढ़ा रहा सहकारिता आंदोलन 26

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार जागरण
अक्टूबर 2025, अंक 07, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. सुधीर महाजन
संपादक
राजीव शर्मा
समूह संपादक
वेद प्रकाश सेतिया

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें :
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com

प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली : 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते :

MINISTRY OF COOPERATION

CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

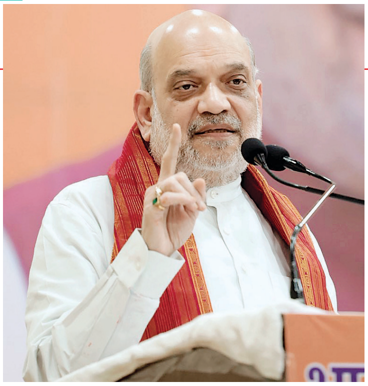

आवरण कथा 08

एनसीईएल के माध्यम से ही निर्यात करें सभी सहकारी संस्थान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार बहुआयामी प्रयास कर रही है।

12

देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी

देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है। बिहार की प्रगति के लिए पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र का विकास बेहद जरूरी है। अब यह क्षेत्र विकास के केंद्र में है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम से करीब 18 लाख लोगों को मिला रोजगार 14

लघु उद्यमियों, दुकानदारों, किसानों और पशुपालकों का कल्याण सर्वोपरि 16

यमुना जी को वर्ष 2029 से पहले स्वच्छ करेगी सरकार : श्री शाह 18

दिव्यांगजनों के कौशल को पहचान उन्हें उचित मंच प्रदान कर रही सरकार 20

जीएसटी सुधार से नागरिकों के सपने होंगे पूरे 23

राष्ट्र के विकास की प्रेरक शक्ति बन रहा पूर्वोत्तर : पीएम श्री मोदी 24

28

एकजुटता व नवाचार से किसानों ने कायम की सफलता की मिसाल

वैश्विक निर्यात में एनसीईएल की बढ़ती भागीदारी

सहकारिताएं हमारे देश के ग्रामीण हिस्से में आर्थिक परिवर्तन की धुरी हैं। गांवों के समग्र विकास की दिशा में सहकारी क्षेत्र के तेजी से विस्तार और विकास ने विकास की नई संभावनाओं को गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही उनके "सहकार-से-समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने व्यापक सुधारों को तेज करते हुए सौ से अधिक महत्वपूर्ण पहल किए हैं, जिनमें देश के सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष संगठन के रूप में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना बेहद अहम है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने देश के संपूर्ण सहकारी क्षेत्र द्वारा निर्यात को तेज करने और सहकारी समितियों को वैश्विक बाजारों का लाभ दिलाने का दायित्व इस बहुराज्यीय समिति को प्रदान किया है। इस सहकारी संस्था के माध्यम से दुनिया भर में हमारी कृषि, बागवानी, डेयरी, अंडे, पशु उत्पादों, मछली, चीनी, मसाले, जैविक उत्पादों, उर्वरकों, हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों, कपड़े, चाय व कॉफी, लघु वनोपज, आयुर्वेदिक व हर्बल औषधियों, प्रोसेस्ड फूड और चमड़ा आदि का निर्यात का तुलनात्मक बेहतर लाभ किसानों को मिल रहा है और उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

एनसीईएल ने अगस्त 2025 तक 13.49 लाख टन कृषि वस्तुओं के निर्यात के माध्यम से 5,403.01 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जिसमें चावल, ताजा लाल प्याज, चीनी, शिशु आहार, प्रसंस्कृत खाद्य, मसाले और चाय आदि शामिल हैं। इस अवधि तक 11,034 सहकारी समितियों को एनसीईएल की सदस्यता मिल चुकी है, जिनमें 10,793 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) और अन्य सहकारी समितियां शामिल हैं।

एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में एनसीईएल निर्यात बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, भ्रष्टाचार, बुनियादी ढांचे की कमी और मानकीकरण जैसी समस्याओं का समाधान करके देश के किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। इससे जहां सहकारिता से जुड़े किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित हो रही है, वहीं नए और विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भागीदारी बढ़ रही है। एनसीईएल का यह योगदान किसानों के बेहतर कल की नींव को मजबूत कर रहा है और वैश्विक परिदृश्य में भारतीय सहकारिता का प्रभाव बढ़ा रहा है।

जय सहकार

विकसित भारत के निर्माण में अहम भागीदारी निभा रहे अन्नदाताओं का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। देशभर के अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी सरकार ने 'दालों में आत्मनिर्भरता मिशन' को मंजूरी दी है। इस ऐतिहासिक पहल से जहां दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं आत्मनिर्भरता के हमारे संकल्प को भी बल मिलेगा। रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे जहां हमारी खाद्य सुरक्षा और मजबूत होगी, वहीं हमारे किसान भाई-बहनों को भी लाभ होगा।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ किसानों की समृद्धि बढ़ाने और पोषण का एक मजबूत स्रोत है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का डेयरी क्षेत्र स्वावलंबन का प्रतीक बना है। चाहे हर पंचायत में सहकारी समितियों की स्थापना का संकल्प हो, श्वेत क्रांति 2.0 हो या नीतिगत पहलें, मोदी सरकार में भारत का डेयरी सेक्टर दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र बन चुका है। डेयरी संयंत्रों के निर्माण में भी देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्वेत क्रांति 2.0 से किसानों की समृद्धि का रास्ता खुल रहा है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना केवल किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह योजना किसानों को केवल उत्पादक ही नहीं, बल्कि सशक्त उद्यमी और आत्मनिर्भर नागरिक बनने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। सरकार का संकल्प है- 'समृद्ध किसान, समृद्ध भारत।'

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

मत्स्य सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से डीप-सी फिशिंग नौकाओं का वितरण देश की मत्स्य सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाते हुए समुद्री मत्स्य क्षेत्र में एक नए युग की शुरूआत करने वाला सिद्ध होगा। समुद्र की गहराइयों में छिपी संपदा का सतत उपयोग और तटीय क्षेत्रों का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री मुरलीधर मोहोल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित 'भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड' (बीबीएसएसएल) किसानों को 'भारत बीज' ब्रांड के तहत उच्च गुणवत्ता वाले बीज समय पर उपलब्ध कराते हुए उनकी आर्थिक समृद्धि को सशक्त बना रही है। संस्था द्वारा विकसित उन्नत किस्म के बीजों के माध्यम से न केवल किसानों की पैदावार बढ़ी है, बल्कि उनकी आय में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही भारत दलहन व तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है।

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

सहकारी चीनी मिलों में अब बनेगा बायोगैस और पोटाश

अहिल्यानगर में शुरू हुआ पहला कारखाना

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करके देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने की शुरुआत की है। भारत में सहकारिता क्षेत्र के भविष्य पर जो सवालिया निशान थे, वे पिछले चार वर्षों में ही पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि कोऑपरेटिव सेक्टर देश के एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहा है। सहकारिता मंत्रालय की उपलब्धियों को उजागर करने वाली इन उपलब्धियों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव में देश के पहले सहकारी मल्टी-फीड कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट के उद्घाटन के मौके पर व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि भारत के सहकारी चीनी मिलों के इतिहास में पहली बार कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और पोटाश ग्रैन्यूल निर्माण इकाई की शुरुआत महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाने में हो रही है। इस नई शुरुआत के तहत भारत सरकार आने वाले दिनों में 15 चयनित चीनी मिलों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की सहायता से ये दोनों संयंत्र स्थापित करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगी। यह शुरुआत आने वाले दिनों में देशभर के चीनी मिलों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी।

- **पहला सहकारी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र प्रतिदिन 12 टन सीबीजी और 75 टन पोटाश का करेगा निर्माण**
- **सहकारी चीनी मिलों को मल्टी-डाइमेंशनल और नॉन-क्रशिंग सीजन में भी मल्टीफीड एथनॉल उत्पादन की सलाह**

भारत के पहले सहकारी कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र की इस परियोजना में लगभग 55 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह सीबीजी संयंत्र प्रतिदिन 12 टन सीबीजी का उत्पादन करेगा और गुड़ से 75 टन पोटाश का निर्माण करेगा। श्री शाह ने कहा कि भारत ये दोनों उत्पाद वर्तमान में विदेशों से आयात करता है और इस नई शुरुआत से हम इस आयात को बंद करके आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना सर्कुलर इकोनॉमी का एक आदर्श उदाहरण बन गया है।

इथेनॉल संयंत्रों को बहुआयामी बनाने पर जोर

इथेनॉल संयंत्रों को बहुआयामी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा कि सहकारी शक्कर कारखानों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी और अब शक्कर कारखानों की सर्कुलर इकोनॉमी

को शत प्रतिशत लागू करने की शुरुआत भी महाराष्ट्र से ही हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भी इसमें राज्य का सहयोग करेगी। श्री शाह ने प्रेरित करते हुए कहा कि महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना द्वारा स्थापित यह उदाहरण महाराष्ट्र की सभी चीनी मिलों के लिए एक मिसाल बननी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में चीनी मिलों को संचालित करने में व्यापक लाभ प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि भारत का पहला गन्ना-आधारित इथेनॉल संयंत्र भी यहीं स्थापित किया गया था। सभी चीनी कारखानों को फलों का प्रोसेसिंग करने का आह्वान करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे फलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा और चीनी कारखानों का लाभ भी बढ़ेगा।

देश के किसानों के प्रति समर्पित है मोदी सरकार

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के किसानों के प्रति समर्पित है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' की शुरुआत की, जिसके तहत अगले छह वर्षों में 11,440 करोड़ रुपए का उपयोग दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाएगा। श्री शाह ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के साथ पंजीकरण कराने वाले किसानों की अरहर, उड़द और मसूर की पूरी दलहन फसल भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद लेगी। इससे महाराष्ट्र सहित देश के सभी किसानों को लाभ होगा।

श्री शाह ने कहा कि देश के दो करोड़ किसानों से हम शत प्रतिशत एमएसपी पर दलहन खरीदेंगे। इसके साथ ही, एक हजार प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी और 88 लाख उच्च गुणवत्ता वाले बीज किट भी वितरित किए जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में ही प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में मसूर की एमएसपी में 300 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों की एमएसपी में 250 रुपए प्रति क्विंटल, चने की एमएसपी में 225 रुपए प्रति क्विंटल, जौ की एमएसपी में 170 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं की एमएसपी में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में ज्वार व बाजरा की एमएसपी में ढाई गुना और तुअर (अरहर), मूंग, सोयाबीन व कपास की एमएसपी में दोगुना वृद्धि की है।■

देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आह्वान

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आह्वान किया है और कहा है कि यदि 140 करोड़ भारतीय नागरिक और देश के सभी व्यापारी यह संकल्प लें कि वे न तो विदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे और न ही उनका व्यापार करेंगे, तो स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी से हमारी अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति प्राप्त होगी। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंचाया है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमें विश्व में प्रथम स्थान हासिल करना है, तो स्वदेशी अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। श्री शाह ने देश के प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया।

सहकारी गन्ना मिलों को सशक्त बनाकर किसानों का कल्याण कर रही मोदी सरकार: श्री अमित शाह

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर तेजी से प्रगति कर रहा है। सहकारी चीनी मिलों की संख्या में 67 की वृद्धि हुई है, चीनी उत्पादन में 10 लाख टन की बढ़ोत्तरी हुई है, डिस्टलरी दो गुना बढ़ी है, इथेनॉल उत्पादन क्षमता पांच गुना और इसकी आपूर्ति 10 गुना बढ़ी है। इसके अलावा पेट्रोल में एथनॉल की ब्लेंडिंग बीस प्रतिशत तक पहुंच गई है। इन तथ्यों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यापुर में पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल जी व पद्मभूषण बालासाहेब विखे पाटिल जी की प्रतिमाओं के अनावरण के मौके पर साझा किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि राज्य और देश की जनता ने किसानों की चिंता करने वाली सरकार चुनी है। मोदी सरकार ने किसानों का 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर माफ करने का सबसे बड़ा काम किया है। टैक्स सेटलमेंट में कोऑपरेटिव सेक्टर को कॉरपोरेट्स के समान स्थान दिलाया है। सरकार की पहल से अब सहकारी चीनी मिलों पर हर साल 4,400 करोड़ रुपए का बोझ नहीं आएगा। सहकारिता मंत्रलाय की पहल पर सहकारी चीनी मिलों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) ने योजना बनाकर अच्छी चीनी मिलों को फाइनेंस किया है।

श्री शाह ने सहकारिता चीनी मिलों का आह्वान किया कि वे अपने इथेनॉल संयंत्र को मल्टीफीड इथेनॉल संयंत्र बनाएं और नॉन-क्रशिंग सीजन में भी मल्टीफीड इथेनॉल का उत्पादन करें। इनमें सब्जियों के कचरे, मक्का और चावल से इथेनॉल बनाएं। इसके लिए जरूरी वित्तीय सहायता एनसीडीसी उपलब्ध कराएगी। श्री शाह ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों को फ्रोजन सब्जी, फल, जूस, फ्रूट पल्प आदि बनाने के लिए भी विस्तार करना चाहिए। श्री शाह ने सहकारी चीनी मिलों को नेफेड और एनसीसीएफ के साथ अनुबंध कर उन्हें मल्टीडायमेंशनल बनने की प्रेरणा दी और कहा कि सरकार ने इथेनॉल खरीद में सभी कोऑपरेटिव्स को प्राथमिकता दी है और एनसीडीसी की ऋण योजना से उन्हें 10 हजार करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। श्री शाह ने कहा कि अभी हाल ही में मोदी सरकार ने 395 चीजों पर जीएसटी को कम किया है, जिसमें शीरा पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इनमें खाने पीने की लगभग सभी चीजों पर जीएसटी शून्य होने से देश की जनता, विशेषकर माताओं-बहनों को फायदा हुआ है।

- **डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल व बालासाहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का किया अनावरण**
- **सहकारिता, ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण में बड़ा योगदान**

श्री शाह ने पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल और पद्मभूषण बालासाहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण कर कहा कि इन दोनों विभूतियों का सहकारिता, ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण में बहुत बड़ा योगदान है। पद्मश्री विखे पाटिल ने अपना पूरा जीवन किसानों के कल्याण में लगा दिया। उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहली कोऑपरेटिव चीनी मिल शुरू किया, जिससे न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के किसान समृद्ध हुए। वास्तव में, वे भारत के सहकारिता के आदिपुरुषों में से एक थे, जिन्होंने चीनी मिलों का मुनाफा व्यापारियों के घर जाने के बजाय किसानों के बैंक अकाउंट में जाने की व्यवस्था की। श्री शाह ने कहा कि पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल, धनंजय राव गाडगिल और बैकुंठ भाई मेहता की त्रिमूर्ति ने महाराष्ट्र में सहकारिता की नींव डाली। पद्मश्री डॉ. पाटिल के सुपुत्र डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल ने न सिर्फ कोऑपरेटिव को मजबूत किया, बल्कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कोऑपरेटिव के मुनाफे से विकास करने की नई परंपरा शुरू की। वे सात बार सांसद चुनकर आए और अटल जी की सरकार में काम भी किया। श्री शाह ने कहा कि उनकी पहल पर रिजर्व बैंक ने माधोपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को एक 'रिवाइवल पैकेज' दिया, जिससे गुजरात के 225 कोऑपरेटिव बैंकों को बचाया जा सका। ■

एनसीईएल के माध्यम से ही निर्यात करें सभी सहकारी संस्थान

- 5,403 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 13.49 लाख टन से अधिक कृषि वस्तुओं का विश्व स्तर पर 28 देशों में किया निर्यात
- चावल, ताजा लाल प्याज, चीनी, शिशु आहार, प्रोसेस्ड फूड, मसाले और चाय सहित कृषि वस्तुओं का एक्सपोर्ट

कोऑपरेटिव सेक्टर का निर्यात लक्ष्य दो लाख करोड़ रुपए

एनसीईएल ने अब तक 11,000 से अधिक सहकारी समितियों को दी सदस्यता

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार बहुआयामी प्रयास कर रही है। श्री मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य की दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय सहकारी संस्था स्थापित करने का निर्णय लेकर नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) स्थापित किया। देश के संपूर्ण सहकारी क्षेत्र से निर्यात के उद्देश्य से एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई यह शीर्ष सहकारी संस्था किसानों, सहकारी समितियों और ग्रामीण उत्पादकों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की एक दूरदर्शी पहल है। श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि एनसीईएल का उद्देश्य विशेष रूप से कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिससे किसानों का व्यापक बाजारों तक पहुंच बने और उसका लाभ मिल सके। निर्यात में रुचि रखने वाली प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियां एनसीईएल की सदस्य बन रही हैं। निर्यात बाजारों से संपर्क स्थापित करके एनसीईएल सहकारी समितियों को मजबूती देने और उन्हें जीवंत आर्थिक संस्थाओं में बदलने के साथ ही कृषि वस्तुओं के लिए नए बाजारों की खोज करने के क्षेत्र में समर्पित होकर कार्य कर रही है। किसानों को निर्यात बाजारों से जोड़ने, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों का समाधान करने, कृषि वस्तुओं के लिए निर्यात प्रमाणन हासिल करने और सुचारू रसद सुनिश्चित करने की दिशा में एनसीईएल अहम योगदान कर रही है। सहकारी कृषि निर्यात के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी संस्था सरकारी समर्थन और शीर्ष सहकारी प्रमोटरों के सहयोग की मजबूत नींव के साथ

बनी है और अब एनसीईएल भारत की सहकारी समितियों का वैश्विक चेहरा बनने के लिए तैयार है। यह पहल ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ सहकारिता आंदोलन में नई ऊर्जा और अवसरों का संचार कर रही है।

एनसीईएल भारत की कृषि एवं सहकारिता व्यवस्था को नई दिशा और मजबूती प्रदान कर रही है। यह भारत के सहकारी क्षेत्र के विकास की दिशा में एक नए युग का सूत्रपात करता है और विदेशी बाजारों में हमारे संपूर्ण सहकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एनसीईएल के माध्यम से भारतीय किसान अब अपनी कृषि उपज का निर्यात सीधे वैश्विक दुनिया और विकसित देशों तक कर रहे हैं। इसका लक्ष्य बेहतर मांग और उचित मूल्य देखते हुए भारतीय सहकारी समितियों से अधिशेष उपज को वैश्विक बाजारों में ले जाना है। यह खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रमाणन और मार्केटिंग को संभालकर निर्यात में मदद करता है। इसके साथ-साथ एनसीईएल वित्तीय व्यवस्था करता है, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है, कौशल निर्माण में मदद करता है, बाजार की जानकारी विकसित करता है और सदस्यों को सरकारी योजनाओं से जोड़ता है। इस तरह यह सहकारी समितियों की क्षमता को मजबूती प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उनकी मौजूदगी का विस्तार करता है। दरअसल, एनसीईएल के जरिए सहकारी मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया है, जिससे स्थानीय सहकारी कृषि उपज और कौशल को दुनिया भर में बाजार खोजने में सक्षम बनने की शक्ति मिली है। इस तरह से सहकारी उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़कर एनसीईएल ने 'मेक इन इंडिया' की विचारधारा को मजबूत किया है, बाजार संबंधों को समृद्ध किया है और सहकारी क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर पैदा किया है।

सहकारिताएं देश के ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन की कुंजी : श्री शाह

श्री शाह ने कहा कि सहकारिताएं देश के ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन की कुंजी हैं। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में, जहां समानता के साथ विकास की संभावना है, सहकारी समितियां विशेष रूप से सहायक हैं। उन्होंने कहा कि एनसीईएल के लिए दो लाख करोड़ रुपए के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत सहकारी समितियों को वैश्विक स्तर पर सोचने और स्थानीय स्तर पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने पहल किया है। इससे दुनिया भर में कृषि, बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, मसाले, जैविक उत्पाद, उर्वरक, हथकरघा, हस्तशिल्प, कपड़ा, चाय व कॉफी, लघु वनोपज, आयुर्वेदिक व हर्बल औषधियां, प्रोसेस्ड फूड और चमड़ा आदि क्षेत्रों में निर्यात के जरिए हमारे किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। श्री शाह ने निर्देश दिया है कि सभी सहकारी संस्थानों का निर्यात एनसीईएल के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि करीब 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार और शुद्ध लाभ सहकारी

समितियों में वापस आ सके। उन्होंने दालों के आयात के लिए अफ्रीका और म्यांमार में एनसीईएल कार्यालय स्थापित करने और सहकारी सदस्यों को वैश्विक मांग को समझने और उनकी आपूर्ति क्षमता प्रदर्शित करने में मदद करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट विकसित करने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने सहकारी समितियों की शक्तियों का लाभ उठाने और उन्हें सफल एवं जीवंत व्यावसायिक उद्यमों में बदलने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने पर जोर दिया।

सहकारी उत्पादों को वैश्विक बाजारों में पहुंचा रही एनसीईएल

एनसीईएल निर्यात बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, कुप्रथाओं, बुनियादी ढांचे की कमी और मानकीकरण जैसी समस्याओं का समाधान करके सहकारी कृषि उत्पादों को विश्व के लच्छित ग्राहकों तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है। महज दो सालों में एनसीईएल ने लाखों टन उपज का निर्यात किया है और अपनी सदस्यता व्यापक ढ़ंग से बढ़ाते हुए उन सदस्यों के साथ लाभ साझा किया है। देश की इस शीर्ष सहकारी निर्यात समिति ने 28 देशों में अपने निर्यात का विस्तार किया है, जिनमें बासमती और गैर-बासमती चावल, समुद्री उत्पाद (विशेष रूप से झींगा), मोटे अनाज, गेहूं, फल और सब्जियां, पशु उत्पाद, मसाले और वृक्षारोपण उत्पाद प्रमुख हैं। एनसीईएल ने जहां वर्ष 2023-24 के दौरान अपने सदस्य सहकारी समितियों को 20 प्रतिशत लाभांश का भुगतान किया, वहीं वर्ष 2024-25 के लिए 4,283 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 122 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हासिल किया है। ये उपलब्धियां भारत के सहकारी आंदोलन को वैश्विक ताकत में बदलने की एनसीईएल की क्षमता को दर्शाती हैं।

इस दौरान एनसीईएल ने सेनेगल, इंडोनेशिया और नेपाल के 61

आयातकों के साथ रणनीतिक समझौतों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। एनसीईएल ने अहम परिणाम देते हुए अगस्त 2025 तक 11,034 सहकारी समितियों को सदस्यता प्रदान की है, जिनमें 10,793 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स), 216 तहसील व जिला स्तरीय सहकारी समितियां, 10 बहु-राज्य सहकारी सोसायटी, 10 राज्य स्तरीय सहकारिता सोसायटी और पांच प्रवर्तक सहकारी समितियां व संगठन शामिल हैं। इस दौरान एनसीईएल के माध्यम से 13.49 लाख टन से अधिक चावल, ताजा लाल प्याज, चीनी, शिशु आहार, प्रोसेस्ड फूड, मसाले और चाय सहित कृषि वस्तुओं का निर्यात हो चुका है, जिसका मूल्य 5,403 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसी वर्ष संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि एनसीईएल को 16 देशों को 14,92,800 टन गैर-बासमती सफेद चावल, पांच देशों को 8,98,804 टन टूटे चावल, एक देश को 14,184 टन गेहूं, 5,326 टन गेहूं का आटा, 15,226 टन मैदा एवं सूजी और दो देशों को 50,000 टन चीनी निर्यात करने जा रहा है। इसके साथ ही एनसीईएल को 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 2,581 सदस्यता आवेदन भी मिले हैं। ■

एनसीईएल को केंद्र सरकार ने अनुमोदित किया और औपचारिक रूप से 25 जनवरी 2023 को बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया गया। यह अधिनियम उन सहकारी समितियों को नियंत्रित करता है, जो एक से अधिक राज्यों में संचालित होती हैं। यह सदस्यों को स्वेच्छा से सहकारी समितियां बनाने की अनुमति देता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करें। यह कानून स्वयं सहायता, पारस्परिक सहायता और सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। यह सहकारी समितियों को कार्यात्मक स्वायत्तता भी प्रदान करता है और संबंधित मामलों को संबोधित करता है।

एनसीईएल की पहुंच और बाजार में मौजूदगी का विस्तार करने की रणनीतियां

निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एनसीईएल बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां अपना रहा है। इसने राज्य नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और पैक्स के साथ जुड़ने के लिए व्यावसायिक योजनाएं तैयार कीं। एनसीईएल ने सहकारी-आधारित कृषि निर्यात को मजबूत करने के लिए सितंबर 2025 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, गुणवत्ता अनुपालन, बुनियादी ढांचे का समर्थन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी शामिल होगी। यह अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग, बाजार स्थिति, डेटा-संचालित बाजार बुद्धिमत्ता और कमोडिटी-विशिष्ट निर्यात रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

इस दिशा में एक अहम पहल करते हुए किसानों और सहकारी समितियों को निर्यात हेतु तैयार करने के लिए एक कमोडिटी सेमिनार श्रृंखला शुरू की गई, जिसका पहला आयोजन जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश में हुआ। कमोडिटी-विशिष्ट रणनीतियों को डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसियों, रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी कार्यालयों और अन्य हितधारकों के साथ 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके साथ ही, सोशल मीडिया, मार्केटिंग टूल और जागरूकता अभियानों के जरिए ब्रांडिंग और डिजिटल आउटरीच को मजबूत किया गया। विशेष रूप से पैक्स से सदस्यता बढ़ाने के लिए एक 'बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग' (बीपीओ) आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया।

पूर्णिया में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बोले

देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी

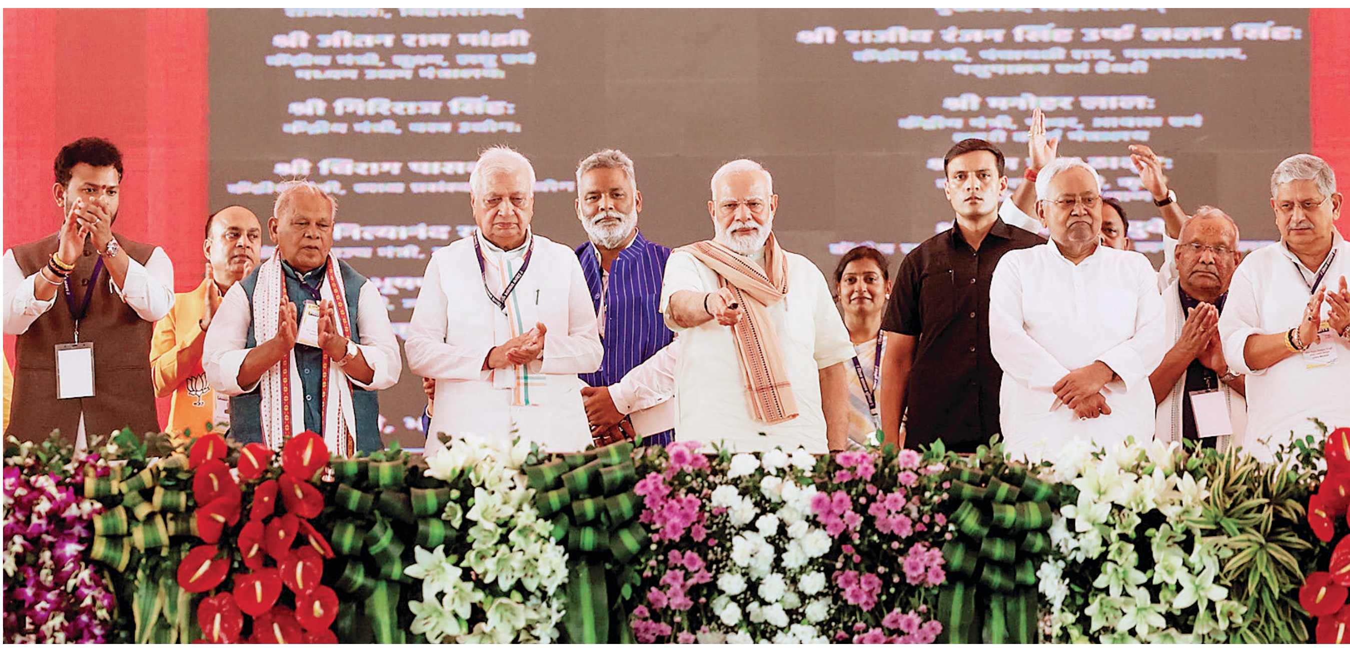

सहकार जागरण टीम

- **नए हवाई अड्डे के शुभारंभ के साथ ही देश के एविएशन मैप पर आ गया पूर्णिया**
- **बिहार में अत्याधुनिक रेल नेटवर्क का बिछाया जा रहा जाल**

देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है। बिहार की प्रगति के लिए पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र का विकास बेहद जरूरी है। अब यह क्षेत्र विकास के केंद्र में है। यह विचार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया जिले में लगभग 40 हजार करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए व्यक्त किया। रेलवे, हवाई अड्डे, बिजली और पानी के क्षेत्रों से जुड़ी इन परियोजनाओं को सीमांचल की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर जरूरतमंद को पक्का घर उपलब्ध कराना उनकी प्रतिबद्धता है। पिछले 11 वर्षों के दौरान उनकी सरकार ने गरीबों के लिए चार करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाए और तीन करोड़ नए घर बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। पिछड़े को प्राथमिकता देना और गरीबों की सेवा करना उनके शासन का मूल उद्देश्य है।

इंजीनियर्स डे का स्मरण करते हुए श्री मोदी विकसित भारत और विकसित बिहार के निर्माण में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन पांच महीने से भी कम के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। उन्होंने टर्मिनल के उद्घाटन की घोषणा की और पहली व्यावसायिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई। नए हवाई अड्डे के शुभारंभ के साथ ही पूर्णिया अब देश के एविएशन मैप पर आ गया है।

पूरे क्षेत्र को अत्याधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ने की बात करते हुए श्री मोदी ने एक वंदे भारत, दो अमृत भारत और एक पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नई अररिया-गलगलिया रेल लाइन के उद्घाटन की घोषणा की और विक्रमशिला-कटरिया रेल लाइन की आधारशिला भी रखी। हाल ही में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर सेक्शन को मंजूरी देने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गेर, जमालपुर और भागलपुर जैसे औद्योगिक केंद्रों को काफी फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है।

बिहार को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। केंद्र और राज्य में उनकी सरकारें किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले चरण के शिलान्यास की भी घोषणा की। मखाना की खेती को बिहार के किसानों की आय का एक प्रमुख स्रोत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने बिहार के लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वादा किया था। इसकी स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बोर्ड मखाना किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करेगा। सरकार ने मखाना क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 475 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है।

बिहार में हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के जारी रहने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने राजगीर में हॉकी एशिया कप की मेजबानी, औंटा-सिमरिया पुल के ऐतिहासिक निर्माण और अफ्रीका को बिहार में निर्मित रेल इंजनों के निर्यात को प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियां करार दिया।

अवैध घुसपैठियों के कारण सीमांचल और पूर्वी भारत में उभर रहे जनसांख्यिकीय संकट के समाधान के लिए जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठ को रोकना उनकी सरकार की ज़िम्मेदारी है। घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और देश इसके अच्छे परिणाम देखेगा।

श्री मोदी ने महिलाओं के 'लखपति दीदी' और 'ड्रोन दीदी' के रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये महिलाएं स्वयं-सेवी समूहों के माध्यम से एक परिवर्तनकारी क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं। महिलाओं के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश कोष जारी किए जाने की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि यह राशि क्लस्टर-स्तरीय संघों तक पहुंचेगी, जो गांवों में स्वयं-सेवी समूहों को सशक्त बनाएंगे। यह पहल महिलाओं को अपनी क्षमताओं और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के नए अवसर प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात की घोषणा करते हुए कहा कि जीएसटी की दरें कम होने से देश में दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। रसोई के खर्चों में काफी कमी आएगी। बच्चों की शिक्षा में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी की लागत भी कम हो जाएगी। बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना आसान होगा।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्णिया के सपूतों द्वारा अंग्रेजों को भारत की ताकत का प्रदर्शन करवाए जाने का स्मरण करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से राष्ट्र ने अपने विरोधियों को वही ताकत दिखाई है। इस ऑपरेशन के रणनीतिक क्रियान्वयन में पूर्णिया के एक वीर सपूत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो या राष्ट्रीय विकास, बिहार देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ■

गुजरात के गांधीनगर में 'स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2025' का उद्‌घाटन कर बोले श्री अमित शाह

स्टार्टअप इकोसिस्टम से करीब 18 लाख लोगों को मिला रोजगार

- **स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप ने बदली करोड़ों गरीबों की जिन्दगी, 17 लाख 90 हजार लोगों को दिया स्थायी रोजगार**
- **'स्टार्टअप इंडिया' लॉन्च होने के आठ वर्षों में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना**
- **वर्ष 2014 में देश में थे केवल 500 स्टार्टअप व चार यूनिकॉर्न, अब मौजूद हैं 1.92 लाख स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न**
- **देश के 48 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाओं द्वारा बने हैं, पूर्वोत्तर में भी 900 स्टार्टअप्स महिलाओं के नेतृत्व वाले हैं**

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'न्यू इंडिया' की संकल्पना के आधार हमारे देश के युवा और स्टार्टअप हैं। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से देश के युवाओं को 'जॉब सीकर' से 'जॉब क्रिएटर' बनाने का स्वप्न पूरा किया है। श्री मोदी ने 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' को हमारे देश की कई समस्याओं के समाधान और युवाओं की सृजनशीलता को प्लेटफॉर्म देने का माध्यम बनाया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सरकार की इन उपलब्धियों को गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 के उद्‌घाटन के दौरान व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि यह कॉन्क्लेव उभरते स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने और विकसित व आत्मनिर्भर भारत की निर्माण यात्रा को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की और पिछले आठ वर्षों में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और आज भारत विश्वस्तरीय 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' बनाने में सबसे तेज गति से आगे निकलने वाला देश बन गया है। देश में स्टार्टअप्स प्रॉफिट कमाने वाली इकाई

से आगे बढ़कर युवाओं की आत्मनिर्भरता और उनके हर स्वप्न को जमीन पर उतारने के लिए का एक बड़ा साधन बन रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि भारत श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले दस सालों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा 'डिजिटल इकोसिस्टम' बन चुका है, जो युवाओं के विचारों, सोच और साहस को तेजी के साथ देश और दुनिया के सामने रखता है। इसका प्रभाव यह है कि वर्ष 2015 में 'इनोवेशन इंडेक्स' में 91वें रैंकिंग से भारत आज 38वें स्थान पर पहुंच गया है। श्री शाह ने विश्वास जताया कि अगले तीन वर्षों में भारत 'ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स' में दस शीर्ष देशों में पहुंच जाएगा और आने वाले दिनों में हम 'वैश्विक इनोवेशन' को कंट्रोल करेंगे। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने शुरुआत से ही स्टार्टअप के लिए सहायक वातावरण तैयार किया है और स्टार्टअप के विकास के लिए वित्तीय, नीतिगत, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और इंडस्ट्रियल सपोर्ट दिया है। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का 'फंड ऑफ फंड्स' स्थापित किया गया, 945 करोड़ कॉर्पस का 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड' शुरू किया, अधिकतम ऋण की सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 20 करोड़ रुपए कर दिया, 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' के लिए 20 लाख रुपए तक देना तय किया और 'प्रोटोटाइप विकास' के लिए 50 लाख रुपए की फंडिंग स्वीकृत किया। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 'मेक इन इंडिया' शुरू किया, 14 प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई लेकर आई, 40 हजार से अधिक कम्प्लायंस को हटाया और 3400 से अधिक कानूनों को आपराधिक कानूनों की श्रेणी से बाहर किया है।

11 वर्षों में एक लाख 92 हजार स्टार्टअप्स और करीब सवा सौ यूनिकॉर्न

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल में भारत में बहुत से परिवर्तन हुए हैं और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार के लिए भी हर क्षेत्र में सकारात्मक कार्य हुए हैं। जहां वर्ष 2014 में देश में केवल 500 स्टार्टअप्स थे, वहीं अब एक लाख 92 हजार स्टार्टअप्स हैं, जो कि 380 गुना अधिक हैं। इसी प्रकार, पिछले वर्षों में यूनिकॉर्न की संख्या भी चार से बढ़कर 120 से अधिक हो गई है, जो कि 350 बिलियन डॉलर से भी अधिक कीमत के हैं। श्री शाह ने यूनिकॉर्न बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के लोगों को हर क्षेत्र में विस्तार करने के लिए स्टार्टअप के साथ जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में आईटी सेक्टर में 21 हजार, हेल्थकेयर में 17 हजार स्टार्टअप्स और कृषि एवं शिक्षा क्षेत्र में 11-11 हजार स्टार्टअप्स हैं। उन्होंने कहा कि भारत के 770 जिलों में भी स्टार्टअप ने अपना दायरा बढ़ाया है और यह बताता है कि देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत मजबूत हो चुका है। देश में वर्तमान समय में टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में ही 52 प्रतिशत स्टार्टअप्स हैं। श्री शाह ने कहा कि 48 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाओं ने बनाए हैं, जिसमें पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले 900 स्टार्टअप्स भी हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने अब तक 17 लाख 90 हजार लोगों को स्थायी रोजगार दिया है।

श्री शाह ने कहा कि गुजरात लगातार चार साल से पूरे देश में स्टार्टअप्स में पहले स्थान पर रहा है। 16 हजार स्टार्टअप्स के साथ गुजरात देश के टॉप पांच राज्यों में शामिल है और 6650 स्टार्टअप्स के साथ अहमदाबाद भी शीर्ष चार शहरों में शामिल है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप हमारे देश के इमर्जिंग सेक्टर्स में सबसे पहले स्थान पर है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सेक्टर की स्पीड, साइज, स्कोप और स्केल में बढ़ोत्तरी की योजना बनाई थी, जो आज जमीन पर उतर रही है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली के संकलन का विमोचन

इस मौके पर श्री शाह ने भारतीय ज्ञान प्रणाली के संकलन का विमोचन किया और कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में आयुर्वेद, शास्त्रीय कलाएं, वास्तुकला, गणित, दर्शन, विज्ञान, अंतरिक्ष और पर्यावरण के क्षेत्र में दुनियाभर का श्रेष्ठ ज्ञान संचित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अनुसंधान और शोध का एक वर्टिकल बनाकर भारतीय युवाओं के लिए इस खजाने को खोला है। इस प्रणाली में उपलब्ध ज्ञान के खजाने को आधार बनाकर हमारे युवा विश्व में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान कर सकते हैं।

जीएसटी सुधारों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी का सरलीकरण और बहुत बड़ा सुधार किया है। देश की आजादी से आज तक इतनी बड़ी टैक्स कटौती पहली बार देश की जनता ने देखी है। श्री शाह ने कहा कि जीएसटी सुधार देश के करदाताओं और सरकार के बीच विश्वास का सेतु बनाने वाला सुधार है। ■

अहमदाबाद में सार्वजनिक समारोह में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

लघु उद्यमियों, दुकानदारों, किसानों और पशुपालकों का कल्याण सर्वोपरि

सहकार जागरण टीम

लघु उद्यमियों, दुकानदारों, किसानों और पशुपालकों का कल्याण सर्वोपरि है। उनकी सरकार इनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और उनका अहित नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए ये बातें कही।

भारत द्वारा आत्मनिर्भरता को विकसित राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला बनाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपने किसानों, मछुआरों, पशुपालकों और उद्यमियों की ताकत के माध्यम से इस मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात में बड़ी संख्या में पशुपालक हैं। भारत का डेयरी क्षेत्र शक्ति का स्रोत है और इसने देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है।

- **डेयरी क्षेत्र शक्ति का स्रोत, इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर**
- **गरीबों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है भारत सरकार**

आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेज गति दे रहा है गुजरात

गुजरात को आत्मनिर्भर भारत अभियान को तीव्र गति प्रदान करने वाला राज्य करार देते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह प्रगति दो दशकों के समर्पित प्रयासों का परिणाम है। गुजरात के एक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने पर पूरा राज्य गर्व महसूस करता है। दाहोद रेल कारखाने में शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बनाए जा रहे हैं। गुजरात में बने मेट्रो कोच अब दूसरे देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। गुजरात में मोटरसाइकिल और कारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां राज्य में कारखाने स्थापित कर रही हैं। वडोदरा ने अब परिवहन विमानों का निर्माण शुरू कर दिया है।

गुजरात को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि हंसलपुर में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण की एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही है। राज्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक प्रमुख नाम बनने की ओर अग्रसर है। गुजरात ने वस्त्र, रत्न और आभूषण उद्योग में अपनी पहचान बनाई है। दवाइयों और टीकों सहित दवा उत्पादन के क्षेत्र में देश का लगभग एक-तिहाई निर्यात गुजरात से होता है।

भारत के सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें गुजरात का योगदान सबसे ज्यादा है। गुजरात हरित ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। देश की पेट्रोकेमिकल आवश्यकताओं को पूरा करने में गुजरात महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लास्टिक उद्योग, सिंथेटिक फाइबर, उर्वरक, दवाइयां, पेंट उद्योग और सौंदर्य प्रसाधन आदि

पेट्रोकेमिकल क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर हैं। गुजरात में पारंपरिक उद्योगों का विस्तार हो रहा है और नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। ये सभी प्रयास आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत कर रहे हैं और रोजगार के अवसर लगातार पैदा कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 20-25 वर्षों में गुजरात की परिवहन संपर्क सुविधा में आमूलचूल परिवर्तन आया है। मेट्रो रेल नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। पिछले 11 वर्षों में राज्य भर में लगभग तीन हजार किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं।

गरीबों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि मजदूर परिवारों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करना उनका मिशन रहा है। कई साल पहले गुजरात में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए स्थायी चारदीवारी से सुरक्षित (गेटेड सोसाइटी) बनाने की पहल की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई आवास परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिनमें झुग्गियों की जगह सम्मानजनक निवास-स्थल बनाए गए हैं और यह अभियान जारी रहेगा।

शहरी गरीबों के जीवन में सुधार को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट-वेंडर) और फुटपाथ पर काम करने वालों की मदद के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, देश भर के लगभग 70 लाख रेहड़ी-पटरी वालों और ठेला चलाने वालों को बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। गुजरात में भी लाखों लाभार्थियों को इस पहल के माध्यम से सहायता मिली है।

पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले बाहर

पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे भारत के लिए गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने देश में एक नए मध्यम वर्ग के उदय में योगदान दिया है। हमारी सरकार नव मध्यम वर्ग और पारंपरिक मध्यम वर्ग, दोनों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है।

जीएसटी प्रणाली में सुधार करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुधार लघु उद्यमियों को समर्थन देंगे और कई वस्तुओं पर टैक्स में कमी लाएंगे। देश भर के व्यवसायी समुदाय और परिवारों को खुशियों का दोहरा उपहार मिलेगा।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत बिजली के बिलों को शून्य पर लाने की बात कहते हुए श्री मोदी ने बताया कि गुजरात में लगभग छह लाख परिवार पहले ही इस योजना से जुड़ चुके हैं। अकेले गुजरात में इन परिवारों को सरकार द्वारा तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की गई है। इससे लाभार्थियों के बिजली बिलों में उल्लेखनीय बचत हुई है।

अहमदाबाद को सपनों और संकल्पों का शहर बनने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज अहमदाबाद अपनी स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। साबरमती रिवरफ्रंट शहर का गौरव बढ़ा रहा है। कांकरिया झील बेहतरीन मनोरंजन स्थलों में से एक बन गई है। झील में नौकायन और किड्स सिटी बच्चों के लिए मनोरंजन और ज्ञान-प्राप्ति का संगम होता है। कांकरिया कार्निवल अब शहर की एक नई पहचान बन गया है।

अहमदाबाद को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में मान्यता दी गया है। शहर में पर्यटन के आधुनिक और अभिनव रूप तेजी से विकसित हो रहे हैं। अहमदाबाद संगीत कार्यक्रमों से जुड़ी अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। एक लाख लोगों की क्षमता वाला अहमदाबाद स्टेडियम एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। ■

दिल्ली सरकार की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर बोले श्री अमित शाह

यमुना जी को वर्ष 2029 से पहले स्वच्छ करेगी सरकार : श्री शाह

सहकार जागरण टीम

- **प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वादा किया है कि 2029 से पहले हम यमुना जी को स्वच्छ करने का काम पूरा कर देंगे**
- **2027 तक दिल्ली कूड़े के पहाड़ से मुक्त हो जाएगी, पिछली सरकार के समय दिल्ली में 65 मीटर ऊंचे कूड़े के पहाड़ थे**

यमुना जी के शुद्धिकरण और साफ यमुना के स्वप्न को साकार करने का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अगले सात महीनों में प्रयागराज तक यमुना जी को स्वच्छ करने की कार्ययोजना बन चुकी है। यमुना के शुद्धिकरण का प्रधानमंत्री श्री मोदी का संकल्प राजनीति नहीं है, बल्कि जनमानस में यमुना जी के प्रति पवित्र भाव का सम्मान करने का कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों तो नई दिल्ली में दिल्ली सरकार की लगभग 1816 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के मौके पर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों से वादा किया है कि हम 2029 से पहले यमुना जी को स्वच्छ करने का काम पूरा कर देंगे। यमुना जी के शुद्धिकरण का यह काम पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को कम करने और विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने को कम करने मात्र से ही हो जाएगा। श्री शाह ने कहा कि हमारी सरकार पांच साल में ही देश की राजधानी को पूरी दुनिया में विकास के कारण प्रसिद्ध करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। श्री शाह ने कहा कि इस आयोजन में शुरू हुए लगभग 80 प्रतिशत काम यमुना जी को निर्मल बनाने की योजनाओं के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की जनता ने परिवर्तन को चुना तब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में सर्वोच्च स्थान पर मां यमुना को शुद्ध करना है।

पिछली सरकार की विकासहीन कार्यप्रणाली पर खेद व्यक्त करते हुए श्री शाह ने कहा कि दिल्ली में पिछले 26 सालों के शासन में दिल्ली की सरकारों के दौरान यहां जनता विकास से महरूम रही है। पिछली सरकार ने कहा था कि वे यमुना को साफ कर उसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने वायदे को भुला दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के शासन

लगातार 24 सालों से देश की सेवा कर रहे श्री मोदी

श्री शाह ने कहा कि हाल ही में श्री मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार काम करते हुए 24 वर्षों की यात्रा पूरी की है। श्री मोदी देश में पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और फिर महान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 24 सालों से देश की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इन वर्षों में अपने सेवाकाल के दौरान अनेक नई शुरूआत की है, जिनसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्नों को पूरा करने की नींव डाली गई है। श्री शाह ने कहा कि देश में सुशासन को जमीन पर उतारने का काम प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया है। उन्होंने देश को सुरक्षित करने, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने और 2047 में देश की आजादी की शताब्दी के समय हर क्षेत्र में देश को सर्वप्रथम बनाने का संकल्प लिया है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ था और उस दिन भी

दिल्ली में 1700 करोड़ रूपए से अधिक की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन हुआ। सेवा पखवाड़ा के समापन पर भी दिल्ली में 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 योजनाओं का लोकार्पण और 8 योजनाओं का शिलान्यास सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को सिद्ध कर रहा है।

में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 65 मीटर तक ऊंचे हो गए थे। श्री शाह ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि एक जनवरी, 2028 को दिल्लीवासियों कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा, बल्कि उन स्थानों पर सुंदर बगीचे का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दिल्ली की जनता को जिन भी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहा, दिल्ली की पिछली सरकार उन्हें रोक कर बैठी रही। श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के जरिए दिल्ली वासियों को भी पांच लाख रूपए तक के मुफ्त इलाज योजना के फायदे को पिछली सरकार ने लागू नहीं होने दिया और दिल्ली की जनता को इसका लाभ नहीं मिल सका। श्री शाह कहा कि दिल्ली में नई सरकार के गठन के पहले सप्ताह में ही यहां आयुष्मान योजना को लागू कर दिया गया।

जनता को समर्पित है मोदी सरकार

पिछली सरकार द्वारा खोले गए 57 मोहल्ला क्लीनिक में ग्लूकोमीटर ही नहीं थे, 45 क्लीनिक में एक्स-रे मशीन भी नहीं थीं, और 21 क्लीनिक में तो पल्स नापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था नहीं थी। इतना ही नहीं, 38 मोहल्ला क्लीनिक में थर्मोमीटर तक उपलब्ध नहीं था। श्री शाह ने कहा कि ऐसे मोहल्ला क्लीनिक में किसी का इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने 11 साल में मोहल्ला क्लीनिक, सीएनजी, शराब, विज्ञापन, दवा, क्लासरूम, दिल्ली जल बोर्ड, शीशमहल, सीसीटीवी और पैनिक बटन जैसे कई घोटाले किए। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के सेवाकाल से पहले केंद्र सरकार ने भी 12 लाख करोड़ रूपए के घपले-घोटाले किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी के 11 साल के शासन में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है, जो यह बताता है कि हमारी सरकारें जनता को समर्पित सरकारें होती हैं।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन ही 395 से अधिक चीजों की जीएसटी दरों में कमी कर या तो उन्हें शून्य कर दिया या पांच प्रतिशत कर दिया। सरकार ने इससे पहले वर्ष 2025-26 के बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को आयकर से मुक्त कर दिया। इन दोनों पहल को एक साथ देखें तो जनता को लगभग ढाई लाख करोड़ रूपए की बचत हुई है। ■

जोधपुर में 'श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय' में बोले श्री अमित शाह

दिव्यांगजनों के कौशल को पहचान उन्हें उचित मंच प्रदान कर रही सरकार

सहकार जागरण टीम

- **प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द देकर सभी दिव्यांगजनों को आत्मसम्मान और नई पहचान दी**
- **मोदी सरकार ने 10 वर्षों में 31 लाख से अधिक लोगों को कृत्रिम सहायता अंग प्रदान किया**

जब दिव्यांगों को दया की जगह दिव्यता का प्रतीक मानने की शुरुआत होती है, तभी सच्चे अर्थों में दिव्यांगजनों के लिए काम होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष रूप से सक्षम लोगों को 'दिव्यांग' कहकर उन्हें देखने के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया। उन्होंने देश के सभी दिव्यांगों के अंदर दिव्यांग शब्द से नए आत्मसम्मान, नई पहचान और आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न जगाया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को राजस्थान के जोधपुर में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के लिए भवन और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के शुभारंभ के मौके पर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में पहली बार विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग करना शुरू किया और श्री मोदी के इस फैसले ने भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों और देश की जनता का दिव्यांगजनों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के बजट को 2014 के 338 करोड़ से रुपए से बढ़ाकर 1,313 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। भारत सरकार ने वर्ष 2014 तक सिर्फ सात लाख लोगों को कृत्रिम अंग और यंत्र दिए थे, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में 18 हजार शिविर लगाकर 31 लाख लोगों को कृत्रिम सहायता अंग प्रदान किया है।

सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सुगम्य भारत अभियान के तहत भारत सरकार के 1314 भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया है, जिसपर 563 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही, 1748 दूसरी इमारतों को भी दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया है। मोदी सरकार ने 35 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों को भी दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया है।

मोदी सरकार ने देश के सभी दिव्यांगजनों के खेल कौशल को प्लेटफॉर्म दिया है। श्री शाह ने कहा कि विश्व में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हुई और तब से 2012 तक हुए सभी पैरालंपिक खेलों में भारत को सिर्फ आठ पदक मिले थे। वहीं, पिछले तीन पैरालंपिक खेलों में भारत ने 52 पदक जीते और इससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। इतने पदक जीतना इस बात को दर्शाता है कि दिव्यांगजन सब कुछ कर सकते हैं, बस जरूरत है उनका हाथ थामने, उनके अंदर की शक्ति को पहचान कर उन्हें उचित मंच प्रदान करने की। उन्होंने कहा कि समाज, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर अगर दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए काम करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है।

पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय 2022 में राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय बना। वहां करीब 15 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं का शुभारंभ कर श्री शाह ने कहा कि इस संस्था के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार इन परियोजनाओं का काम समय पर पूरा होगा, जिससे सैकड़ों बच्चों के जीवन में नया उजियारा आएगा। उन्होंने कहा कि सुशीला जी ने पांच विद्यालयों, दो महाविद्यालयों, निःशुल्क छात्रावास, भोजन, ऑडियो बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन रीडर, कम्प्यूटर लैब और पुस्तकालय के माध्यम से दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं के जीवन में ज्ञान और दृष्टि का प्रकाश प्रसारित किया है और दिव्यांगों के जीवन को सरल बनाया है। ■

गोवा में 'म्हाजे घर योजना' व अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण कर बोले श्री अमित शाह

गोवा सरकार ने 10 लाख लोगों को घर का मालिक बनाया

- एक कुशल प्रशासक, संवेदनशील सरकार और प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के सुधारों की परिचायक है 'म्हाजे घर योजना'
- 2,452 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास राज्य के विकास में एक बड़ी छलांग

सहकार जागरण टीम

गोवा में शुरू हो रही 'म्हाजे घर योजना' सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि एक कुशल प्रशासक, संवेदनशील सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुधारों के लिए हमारी सरकारों की मेहनत का परिचायक है। लगभग 11 विभिन्न प्रकार की कानूनी जटिलताओं में उलझे गोवा के लाखों नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान करना सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को गोवा के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की प्रमुख कल्याणकारी 'महाजे घर योजना' के शुभारंभ के दौरान व्यक्त किया। इसका उद्देश्य सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करना और लंबे समय से निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करना है।

2,452 करोड़ रुपए से अधिक की 21 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डा. प्रमोद सावंत की सरकार ने कानून बनाकर सभी हाउसिंग विसंगतियों को समाप्त किया है, जिससे कानूनी पचड़े में फंसे 10 लाख नागरिकों को घर का अधिकार मिला है। यह गोवा के विकास में एक बहुत बड़ी छलांग है। इन विकास कार्यों से विकसित गोवा का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि गोवा भारत माता के माथे पर एक बिंदिया के समान है और गोवा के विकसित होने से अनेक राज्य प्रेरणा लेकर विकसित बनेंगे।

सबसे पहले पूर्ण विकसित राज्य बनेगा गोवा

श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने पर श्री मोदी ने सभी राज्यों को प्रेरणा दी कि लोगों की समस्याओं को जानें, उनके दुख को समझें, उन समस्याओं का कानूनी हल निकालें और जरूरी होने पर समाधान के लिए नया कानून लाकर लोगों को उनका अधिकार दें। प्रधानमंत्री की उसी प्रेरणा से हमारी सभी सरकारें देशभर में काम कर रही हैं और इसका नतीजा यह है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को जीवन की सभी आवश्यक सुविधाएं मिल गई हैं। श्री मोदी ने करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश फैलाया है। 11 वर्षों पहले गोवा की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 12 हजार 73 रुपए थी, वर्ष 2023-24 में बढ़कर तीन लाख 57 हजार रुपए हो गई है। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य रखा है, लेकिन गोवा में जिस गति से समस्याओं का समाधान हो रहा है, गोवा सबसे पहले पूर्ण विकसित राज्य बनेगा। ■

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को दी सौगात

जीएसटी सुधार से नागरिकों के सपने पूरे होंगे

सहकार जागरण टीम

राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) सुधार भारत की विकास गाथा को गति प्रदान करेंगे। कारोबारी गतिविधियां आसान होंगी। निवेश के आकर्षित होने से विकास की दौड़ में प्रत्येक राज्य समान भागीदार बनेंगे। राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को कर सुधारों की सौगात देते हुए कहा कि सभी वर्ग और समुदाय की चिंताओं का ध्यान रखा गया है।

वर्ष 2017 में कर सुधारों की दिशा में पहला कदम उठाए जाने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने लोगों और राष्ट्र के हित में जीएसटी को प्राथमिकता दी। सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हर प्रश्न का समाधान किया गया है। देश को विभिन्न करों के जाल से मुक्त करते हुए पूरे देश में एक समान व्यवस्था स्थापित हुई। एक राष्ट्र-एक कर का सपना साकार हुआ।

सुधार को एक सतत प्रक्रिया बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे समय बदलता है और राष्ट्रीय आवश्यकताएं विकसित होती हैं, अगली पीढ़ी के सुधार भी उतने ही आवश्यक हो जाते हैं। देश की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नए जीएसटी सुधार लागू किए जा रहे हैं। नए जीएसटी ढांचे के अंतर्गत मुख्य रूप से केवल 5 और 18 प्रतिशत के कर स्लैब ही रहेंगे। रोजमर्रा की ज्यादातर वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। खाने-पीने की चीजें, दवाइयां, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी कई वस्तुएं और सेवाएं या तो कर-मुक्त होंगी या केवल पांच प्रतिशत कर ही लगेगा।

- **नागरिकों की सेवा का सार अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवाकर सुधारों में स्पष्ट रूप से होता है प्रदर्शित**
- **वस्तु व सेवाकर में अब केवल दो स्लैब 5 व 18 प्रतिशत ही रहेंगे**

पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ भारतीयों के गरीबी से उबरने और देश की प्रगति में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नव-मध्यम वर्ग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ग की अपनी आकांक्षाएं और सपने हैं। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त करके आयकर में राहत का तोहफा दिया है। अब गरीबों और नव-मध्यम वर्ग को लाभ मिलने की बारी है। जीएसटी की घटी दरों से नागरिकों के लिए अपने सपनों को पूरा करना आसान हो जाएगा। चाहे घर बनाना हो, टीवी या रेफ्रिजरेटर खरीदना हो, या स्कूटर, बाइक या कार खरीदना हो, अब सब कम खर्च में होगा। यात्रा भी अधिक किफायती हो जाएगी, अधिकांश होटल कमरों पर जीएसटी कम कर दिया गया है।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों में 'नागरिक देवोभव' का मंत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि आयकर राहत और जीएसटी कटौती को मिला दिया जाए तो पिछले वर्ष में लिए गए निर्णयों से भारत के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। इसी कारण वे इसे 'बचत उत्सव' कहते हैं।

विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलने की अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक बड़ी ज़िम्मेदारी एमएसएमई - भारत के सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योगों पर है। जो कुछ भी लोगों की जरूरतों को पूरा करता है और देश के भीतर निर्मित किया जा सकता है, उसका उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जाना चाहिए।■

राष्ट्र के विकास की प्रेरक शक्ति बन रहा पूर्वोत्तर : पीएम श्री मोदी

सहकार जागरण टीम

- वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण भूमिका
- अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन

पूर्वोत्तर के आठ राज्य अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजनीय हैं। विकास की यात्रा में इन्हें पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। यह क्षेत्र राष्ट्र के विकास की प्रेरक शक्ति बनकर उभर रहा है। यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन करते हुए कही।

सरकार के लिए नागरिकों का कल्याण सर्वोपरि होने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीवन को सरल बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग, यात्रा की कठिनाइयों को कम करने के लिए ईज ऑफ ट्रैवल, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार करने के लिए ईज ऑफ लिविंग ट्रीटमेंट, शिक्षा में सहायता के लिए ईज ऑफ एजुकेशन और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए ईज ऑफ डूईंग बिजनेस पर काम किया जा रहा है। अच्छी सड़कों का निर्माण हो रहा है। सेला सुरंग जैसा बुनियादी ढांचा, जिसे कभी असंभव माना जाता था, अब अरुणाचल प्रदेश की प्रगति का प्रतीक बन गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल न केवल उगते सूरज की भूमि है, बल्कि देशभक्ति की भी धरती है। तवांग मठ से लेकर नामसाई के गोल्डन पैगोडा तक अरुणाचल प्रदेश शांति और संस्कृति के संगम का प्रतिनिधित्व करता है। यह पवित्र भूमि भारत माता का गौरव है। अरुणाचल प्रदेश व पूर्वोत्तर के सुदूर इलाकों में हेलीपोर्ट स्थापित किए जाने व इन क्षेत्रों को उड़ान योजना के अंतर्गत अंगीकृत करने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि होलोंगी हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल भवन बनाया गया है, जहां से अब दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। इससे फलों, सब्जियों और अन्य उत्पादों को देश भर के प्रमुख बाजारों तक पहुंचाना अब बहुत सुगम हो गया है।

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा यह विजन तभी साकार हो सकता है, जब प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप प्रगति करें। पूर्वोत्तर इन लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने 2030 तक सौर, पवन और जल विद्युत सहित गैर पारंपरिक श्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है और अरुणाचल प्रदेश समेत पूरा पूर्वोत्तर इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम योगदान दे रहा है।

भारत सरकार द्वारा शुरू वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को सीमावर्ती गांवों के लिए एक मील का पत्थर बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अरुणाचल के विकास में महत्वपूर्ण रूप से सहायक है।

अरुणाचल प्रदेश कृषि और बागवानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। किवी, संतरा, इलायची और अनानास जैसे स्थानीय उत्पाद राज्य को एक नई पहचान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का महत्व बताते हुए कहा कि इस मंत्र का पालन करने से अरुणाचल प्रदेश व पूरे पूर्वोत्तर का विकास गति पकड़ेगा। ■

नेशनल कोऑपरेटिव कांफ्रेंस में बोले सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर

किसानों को राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों से जोड़ रही सहकारिता

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प के अनुरूप भारतीय सहकारिता विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम योगदान करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता एक सशक्त आर्थिक आंदोलन के रूप में उभर रही है और किसानों, महिलाओं व युवाओं के जीवन में नए अवसर और समृद्धि ला रही है। केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इन विचारों को हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा शिमला में आयोजित 'राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन -2025' में व्यक्त किया। सामूहिक सहकारी शक्ति के माध्यम से भारत के भविष्य को आकार देने के उद्देश्य से 'सहकारी पुनर्जागरण' की थीम पर आधारित राष्ट्रीय जमावड़े में श्री गुर्जर ने कहा कि सहकारिता भारत की सामूहिक शक्ति है और यही शक्ति आत्मनिर्भर हिमाचल एवं सशक्त भारत का भविष्य तय करेगी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सहकारी समितियों के सशक्तीकरण, पारदर्शिता और नवाचार को नया आयाम देने वाला साबित होगा।

सहकारिता क्षेत्र में किसानों के हितों, महिला सशक्तीकरण और नवाचारों को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए सहकारिता राज्यमंत्री श्री गुर्जर ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक भंडारण, कोल्ड चेन सुविधाओं और निर्यात अवसरों की आवश्यकता जताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि सहकारी मॉडल सस्ती ऋण सुविधा, आधुनिक तकनीक और महिलाओं व युवाओं के लिए स्व रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की खाई को पाटता है। एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल जैसी संस्थाएं हिमालयी किसानों को राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों से जोड़ रही हैं। देश के सहकारी ढांचे को सुदृढ़ व तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में सहकारिता मंत्रालय ने 100 से अधिक महत्वपूर्ण पहल किए हैं, जिससे सहकारिता ग्रामीण विकास के मुख्य आधार के रूप में उभर रही है।

एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल जैसी संस्थाओं की व्यापक भूमिका से बदल रही तस्वीर

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान यह दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन देश में सहकारी विकास को गति देने के लिए राष्ट्रव्यापी गतिविधियों का ही एक हिस्सा था, जहां सहकारिता क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया और भविष्य की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान सहकारी मेला और फिनटेक कॉरपोरेट प्रदर्शनी के माध्यम से बैंकिंग तकनीक, डेयरी, कृषि और बागवानी से जुड़े नवाचार भी प्रदर्शित किए गए। सम्मेलन में सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत हुआ और कहा गया कि यह एक बड़ा कदम है जो सहकारी आंदोलन को शैक्षणिक और संस्थागत मजबूती प्रदान करेगा। इससे संबद्ध संस्थान और कॉलेज इस क्षेत्र में विशेष पाठ्यक्रम शुरू कर सकेंगे।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत सहित भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा, नाबार्ड के डीएमडी श्री गोवर्धन रावत, इफको एवं एनसीयूआई के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी और अमूल, नाफेड, एनसीडीसी समेत अन्य प्रमुख सहकारी संस्थाओं के अध्यक्षों व प्रबंध निदेशकों, देश की सहकारी समितियों और बैंकों के शीर्ष प्रतिनिधियों, वरिष्ठ नीति निर्माताओं, सहकारी नेताओं व अधिकारियों के साथ शिक्षाविद और तकनीक विशेषज्ञों ने सम्मेलन में भाग लिया। ■

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की राष्ट्रीय कार्यशाला

'सहकार से समृद्धि' के विजन को आगे बढ़ा रहा सहकारिता आंदोलन

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण के अनुरूप सहकारिता मंत्रालय सहकारी आंदोलन को नई दिशा प्रदान कर रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आज सहकारिताएं कृषि और ऋण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवा, सेवाओं और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण जैसे क्षेत्रों में भी फैल गई हैं। सहकारी समितियों को जन-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए मंत्रालय सहकारी क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को संस्थागत और मानव क्षमता विकास के साथ जोड़ने पर जोर दे रहा है। इन विचारों को सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला और समीक्षा बैठक के दौरान सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में साझा किया, जहां सहकारी क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने, पैक्स के पूर्ण डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने, पैक्स कर्मचारियों और सदस्यों की डिजिटल क्षमता का निर्माण करने और पैक्स को कृषि इनपुट, ऋण, खरीद और भंडारण जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के प्रयासों पर जोर दिया गया।

पैक्स, एआरडीबी और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्युटरीकरण की प्रगति की जानकारी साझा की गई। इस दौरान सीआरसीएस ने राज्यों को बहु-राज्य सहकारी समितियों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी

- **सहकारिता संस्थाएं कृषि और ऋण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवा, सेवाओं और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं**
- **पैक्स के पूर्ण डिजिटलीकरण, डिजिटल क्षमता निर्माण, कृषि इनपुट, ऋण, खरीद और भंडारण जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली वन-स्टॉप शॉप के रूप में सक्षम बनाने पर जोर**
- **सभी पंचायतों और गांवों में दो लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण पर फोकस**

साझा की और बेहतर समन्वय के लिए सभी के सहयोग की अपील की। इस मौके पर राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। एनडीसी में 30 क्षेत्रों की 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियां और 32 करोड़ सदस्य शामिल हैं। ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और डिजिटल परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में पैक्स और बहु-राज्य सहकारी समितियों की भूमिका पर जोर देते हुए सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने सहकारी समितियों के प्रभावी प्रशासन के लिए केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने, डिजिटल उपकरणों और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि का लाभ उठाने का आह्वान किया। राज्यों को सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 'सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन और सूचना' के विषय पर काम करने का आह्वान किया गया। इस दौरान,

इफको-टोकियो के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बीमा क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

सहकारी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर

इस मौके पर सहकारी योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन, वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और सहकारी संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया गया और कहा गया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए अपने डेटा को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के साथ साझा करना चाहिए। श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय बैंकिंग से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए पहले से ही काम कर रहा है। सहकारी बैंकों के आय के अवसरों को बढ़ाने और स्थानीय उद्यमिता को मजबूत करने के लिए सहकारी व्यवसायों के विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों, सचिव, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) और सहकारी क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों की उपस्थिति में आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत तीन राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियों- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल), और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की प्रगति की भी समीक्षा की।

अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन में तेजी

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर मंत्रालय का फोकस है। इसे प्रायोगिक चरण में 500 पैक्स से शुरू किया गया और फिर देश भर में 29,000 पैक्स तक बढ़ाया गया है। कार्यशाला में पैक्स के व्यवसाय विविधीकरण के माध्यम से गोदामों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने, भूमि की उपलब्धता, सहकारी शक्ति और मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधार पर पैक्स का मानचित्रण करने और स्थायी संचालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने पर सहकारिता मंत्रालय के फोकस की चर्चा की गई। सभी पंचायतों और गांवों में दो लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन तथा सुदृढ़ीकरण की समीक्षा के दैरान इसमें नए सहकारी गठन के लिए संभावित जिलों और प्रखंडों की पहचान करने, व्यवसाय सक्रिता और विविधीकरण के माध्यम से मौजूदा समितियों को मजबूत करने और ग्रामीण आजीविका सृजन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

देशभर के शीर्ष सहकारी प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 (आईवाईसी-2025) के महत्व पर जोर दिया और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से इसके प्रमुख कार्यक्रमों के सक्रिय आयोजन का आह्वान किया। साथ ही, सभी राज्यों को 'एक पेड़ मां के नाम' नामक राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को आगे बढ़कर सफल बनाने और इस दिशा में सहकारी समितियों की प्रगति पर उनके लिए पुरस्कार स्थापित करने की प्रेरणा दी गई। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान सहकारिता को नई दिशा देने के लिए जनसंपर्क के महत्व पर जोर देते हुए सर्वोत्तम सहकारी प्रथाओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए सोशल मीडिया हैंडल के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। ■

एकजुटता व नवाचार से किसानों ने कायम की सफलता की मिसाल

सहकार जागरण टीम

त्रिपुरा के धलाई जिले के कमलपुर की दुर्गाचौमुहनी किसान उत्पादक संघ ने छोटे व सीमांत किसानों के विकास की राह को बनाया आसान, ग्रामीणों में जगा नया उत्साह

किसानों की एकजुटता एवं नवाचारों से चुनौतियां भी अवसर में बदल रही हैं। छोटे व सीमांत किसानों के संगठित प्रयासों और प्रशिक्षण से जहां बुनियादी स्तर पर बदलाव हो रहा है, वहीं वे सामाजिक समावेश, महिला सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। ग्रामीणों में नया उत्साह जगाने का यह प्रेरक कार्य पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य के धलाई जिले के कमलपुर की दुर्गाचौमुहनी किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) ने किया है, जहां वह किसानों का बाजार संपर्क बढ़ाने के साथ भी बड़े बदलाव ला रहा है। यह एफपीओ न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि राज्य और पूरे भारत के किसानों के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है। करीब तीन साल पहले अस्तित्व में आए इस एफपीओ के करीब आठ सौ सदस्य हैं, जिनमें एक चौथाई महिलाएं हैं। इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की भी बड़ी भागीदारी है। किसानों का यह संगठन अपने सदस्यों को बीज, कीटनाशक, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि उपलब्ध कराकर उनको खाद्य पदार्थों के अधिकतम उत्पादन के लिए प्रेरित करता है और उनके उत्पादों के मार्केटिंग में भी मदद करता है, जिससे बाजार से उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलता है। यह किसानों को विकास के पथ पर अग्रसर करके ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है।

संगठन ने बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई शीर्ष सहकारी संगठनों से समझौता किया है, जिसमें उर्वरक व अन्य चीजों के लिए इफको से और उच्च गुणवत्तायुक्त बीजों के लिए 'वेलनेक्स्ट सीड्स' के साथ समझौता उल्लेखनीय है। इन साझेदारियों से बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित हुआ है। अपने सदस्यों के हित के लिए दुर्गाचौमुहनी एफपीओ ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है और किसानों के उपज को डिजिटल मार्केटप्लेस के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए 'ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कॉमर्स' (ओएनडीसी) में भी नामांकन किया है। इसके अलावा यह टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहा है।

दुर्गाचौमुहनी एफपीओ की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

इस एफपीओ ने अब तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। संगठन के पास कृषि उपकरणों का एक छोटा बैंक हो गया है। उसके पास तीन पावर टिलर, दो पावेर वीडर, 10 स्पेयर पार्ट्स और दो पंप है। इससे किसानों को लाभ हो रहा है और उपज की उत्पादकता व उनकी आय बढ़ रही है। समिति ने 74 लाख रुपए का कारोबार किया है। संगठन ने अपने सदस्यों को कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को मुफ्त इनपुट (बीज व उर्वरक आदि) उपलब्ध कराए हैं, जिससे उनकी लागत कम हुई हैं। समिति ने भविष्य में ड्रोन और सेंसर-आधारित खेती को अपनाने की योजना बनाई है। किसानों के उत्पादों की कीमत बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और पैकेजिंग व ब्रांडिंग की भी तैयारी है। उपज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने के लिए भी काम किया जा रहा है।

कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष जोर

यह किसान उत्पादक संघ अपने सदस्यों व पदाधिकारियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें उन्हें आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाता है और खेती के आधुनिक व नए तरीकों की जानकारी दी जाती है। इसमें कंप्यूटर पर काम करने का प्रशिक्षण और लेखांकन व कानूनी पहलुओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें क्लस्टर आधारित व्यावसायिक गतिविधियों के तहत सामूहिक व्यापार रणनीतियों को लागू करने पर भी फोकस किया जा रहा है। एफपीओ अपने सदस्यों के लिए सरकारी योजनाओं और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से ऋण और अनुदान की व्यवस्था की योजना भी बना रही है। आने वाले दिनों में इसका लक्ष्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग के जरिए ड्रोन और सेंसर-आधारित खेती को अपनाने, अधिक किसानों को संगठन से जोड़ने, प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की स्थापना करके पैकेजिंग और ब्रांडिंग के माध्यम से मूल्यवर्धन करने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को पहुंचाकर किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करना है। ■

डॉ एआर श्रीनाथ

सहकारिता से युवाओं और महिलाओं को जोड़ने पर बल

विश्व में सहकारिता आंदोलन कई मायने में लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। भारत में सहकारिता आंदोलन लोगों के जीवन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता का विस्तार निचले स्तर तक हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा सहकारिता आंदोलन को और भी अधिक मजबूत बनाने की है, जिसमें देश के युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है। महिलाओं, युवाओं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को भी अधिक से अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। विश्व भर की सहकारी समितियों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और महिलाएं सहकारी समितियों में नेतृत्व की भूमिका में आगे आ रही हैं।

भारत के विभिन्न सेक्टरों में साढ़े आठ लाख सहकारी समितियां हैं, जिससे 29 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद देश में बड़ी आबादी को रोजगार की दरकार है। बेरोजगारी खत्म करने और गरीबी दूर करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहकारिता की भूमिका लगातार बढ़ी है, जिसमें महिलाओं की अब महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाएं अब विभिन्न तरह की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा ले रही हैं। सहकारी समितियां महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और पारिवारिक आमदनी में सहयोग करने का माध्यम बन गई है। पंचायती राज कानूनों में संविधान संशोधनों के माध्यम से स्थानीय निकाय और नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बहु राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम 2023 में सहकारी समितियों के निदेशक मंडल में दो महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। डेयरी सहकारी समितियों में महिलाओं का काफी सराहनीय योगदान रहा है। एनसीयूआई द्वारा विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए शैक्षणिक फील्ड प्रोजेक्ट कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

एनसीयूआई विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वे आत्मनिर्भर हो रही हैं। भोपाल, शिमोगा और इंफाल में महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से सशक्त करने के लिए कई कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

छह जुलाई वर्ष 2021 में देश के पहले सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से भारतीय महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इस क्रम में आम बजट में महिलाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपए के बजट का स्वीकृत किया गया, जिससे महिला और लड़कियों के जीवन को बेहतर करने में खर्च किया जाएगा। इससे यह सिद्ध होता कि सरकार आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान को मजबूत करने के अपने संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकास में महिलाओं की सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही लघु, सुक्ष्म और मध्यम स्तर के उद्यमों (एमएसएमई) के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इस संदर्भ में सहकारी क्षेत्र इन योजनाओं को लागू करने में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रहा है। विशेष रूप से महिलाओं के विकास के लिए पंजीकृत सहकारी समितियां जैसे कि महिला कल्याण सहकारी समितियां (जिनमें से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस रिपोर्ट के अनुसार 25,092 हैं) विकास के लिए इन निधियों तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। इसका प्रयोग महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के अधिक आयोजन करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों उद्यमों की बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय युवाओं के लिए भी सहकारिता में बेहतर भविष्य के अपार विकल्प उपलब्ध हैं। भारतीय शहर में हर तीसरा व्यक्ति युवा है, जल्द ही भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनने वाला है, जिसकी 64 प्रतिशत आबादी कामकाजी आयु वर्ग की है। अभी अधिकांश भारतीय युवा शैक्षणिक स्तर पर सहकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हैं।

युवा उत्पाद या सेवा आधारित सहकारी समिति शुरू कर सकते हैं, इससे सहकारिता के संदर्भ में उनकी शिक्षा का अधिक बेहतर उपयोग किया जा सकता है। हालांकि अभी तक युवाओं की सहकारिता में भागीदारी कैंपस गतिविधियों तक ही सीमित हैं, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थानों में युवा छोटी लेकिन जरूरी चीजों की आपूर्ति चेन बनाने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं जैसे कैंपस में कॉपी, किताब, पेन पेंसिल आदि की बिक्री युवाओं की छोटी सहकारी समितियों द्वारा की जा रही है। यह सहकारी समितियां अन्य जरूरी सेवाएं जैसे टिकट बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि सेवाओं का भी संचालन कर रही हैं। बहुत कम जगहों पर यह युवा बचत और ऋण संबंधी गतिविधियों को भी संचालित कर रही हैं। नई सहकारिता नीति से सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना से सहकारिता में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।■

पूर्व निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई)

इफको और इफको नैनोवेंशन्स ने दशहरे के पावन अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में धमार्मृत का शुभारंभ किया। धमार्मृत केले के रस से बना एक अभिनव जैव-उत्तेजक है। इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी, प्रबंध निदेशक श्री केजे पटेल, राजकोट के सांसद श्री पुरुषोत्तम रुपाला, इफको के विपणन निदेशक श्री योगेन्द्र कुमार एवं इफको नैनोवेंशन के प्रबंध निदेशक डॉ ए लक्ष्मण, निदेशक भावेश रादडिया एवं अन्य पदाधिकारियों आयोजन में भागीदारी की।

राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में बैंकिंग परिचालन शुरू करने की भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड (कोबी) के निदेशक मंडल के साथ एक बैठक की, जिसमें बैंकिंग लाइसेंस से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रियाओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की गई।

ब्राजील की डेयरी और कृषि सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उच्च-स्तरीय सहकारी प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली स्थित इफको सदन पहुंचा, जहां उनके आगमन पर इफको के प्रबंध निदेशक श्री केजे पटेल एवं मार्केटिंग डायरेक्टर श्री योगेन्द्र कुमार की उपस्थिति में स्वागत किया गया। भारत और ब्राजील कृषि में सहकारी प्रयासों के माध्यम से एक मजबूत रिश्ता साझा करते हैं।

इफको के प्रबंध निदेशक श्री केजे पटेल ने दुबई में इफको के संयुक्त उद्यम ओमिफको की 118वीं बोर्ड बैठक में भागीदारी की, जो ओमिफको के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में उनकी पहली बोर्ड बैठक थी। श्री पटेल ने ओमिफको को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया।

गुजरात के अमरेली जिला सहकारी बैंक की वार्षिक आम बैठक और 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के दौरान इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी के साथ प्रबंध निदेशक श्री केजे पटेल ने भी भागीदारी की और अमरेली के सभी सहकारी समितियों से आए हुए सहकारी बंधुओं से मुलाकात की।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के फरह में बेरी प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) में इफको के नैनो उर्वरक अभियान के तहत विकासखंड स्तरीय किसान सभा एवं महा सदस्यता अभियान का आयोजन हुआ, जहां इफको पदाधिकारियों ने किसानो को इफको के नैनो टेक्नोलॉजी से बने उत्पादों- इफको नैनो यूरिया प्लस, इफको नैनो डीएपी,सागरिका तरल, एनपीके कंसोटिया के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है, देश तभी आगे बढ़ेगा, जब देश का गरीब गरीबी से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। सरकार का बहुत जोर बहनों-बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर भी है। हमारी करोड़ों बहनें मुद्रा योजना के जरिए लोन लेकर नए व्यापार कर रही हैं और नए उद्योग लगा रही हैं। हमारी सरकार तीन करोड़ ग्रामीण माताओं-बहनों को लखपति दीदी बनाने के अभियान में जुटी है। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इतने कम समय में अब तक करीब-करीब दो करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। हम महिलाओं को बैंक सखी और ड्रोन दीदी बनाकर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं नई क्रांति कर रही हैं।

- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (**CEAS-LMS**) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक: राजीव शर्मा

Postal Registration No: DLHIN/25/A0141
Published on 15.04.2024 Applied for Registration/ Exempted

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ